WFP
World Food Programme

सत्यमेव जयते
NITI Aayog

पौष्टिक अनाजों (मिलेट्स) को मुख्यधारा में लाने के लिए एशिया और अफ्रीका मे प्रचलित अच्छी प्रथाओं के संकलन तथा आदान - प्रदान (एमईजीपी)

वैश्विक खाद्य उत्पादन, आपूर्ति एवं संवितरण में सुधार एव वृद्धि होने के बावजूद कुपोषण और खाद्य असुरक्षा की समस्या बनी हुई है। जलवायु परिवर्तन भी पोषण और खाद्य सुरक्षा के लिए एक खतरा रहा है चूंकि कृषि क्षेत्र हमेशा जलवायु पर निर्भर रहा है। वर्तमान समय में मौसम के बदलते स्वरूपों के चलते कृषि क्षेत्र और भी संवेदनशील हो गया है। वैश्विक तापमान में निरंतर वृद्धि के कारण मौसम का स्वरूप बिगड़ने से भविष्य में अधिक आकस्मिक घटनाओं के होने की आशंका है। ये घटनाएं लाखों आबादी, विशेष रूप से छोटे किसानों की खाद्य और पोषण सुरक्षा में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इस संदर्भ में मिलेट्स, जिसे बहुधा 'पौष्टिक अनाज (न्यूट्रि सीरिअल)' कहा जाता है, पहले से ही खाद्य और पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहन करने की क्षमता के कारण मिलेट्स निश्चित रूप से भविष्य की फसल के रूप मे अहम भूमिका निभा सकते है।

मिलेट्स में आहार विविधता को बढ़ाने की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, हमारे देश में इनकी खेती और खपत में तेज गिरावट देखी जा रही है। वर्ष 1962 से 2010 तक मिलेट्स की प्रति व्यक्ति खपत 32.9 कि.ग्रा से गिरकर 4.2 कि.ग्रा हो गई है[1]।

मांग पक्ष को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक[2]

1. तेज गति से शहरीकरण और बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय के कारण उपभोक्ता की रूचि एवं पसंद में बदलाव आ रहा है।
2. निम्न सामाजिक स्तर और मिलेट्स (विशेषकर ज्वार) आधारित भोज्य पदार्थों को तैयार करने में होने वाली असुविधा/ पारंपरिक ज्ञान की कमी।
3. अनाजों के भंडारण का काम समय।
4. धान और गेहूं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में बड़े पैमाने पर शामिल किया गया है।
5. मिलेट्स को सार्वजनिक वितरण प्रणाली(पीडीएस) में समान रूप से शामिल न होना।

महत्वपूर्ण आपूर्ति पक्ष कारक

1. मूल्य-वर्धित मिलेट्स उत्पादों के लिए औद्योगिक मांग की कमी के कारण किसान मिलेट्स की खेती करने के प्रति हतोत्साहित हैं।
2. प्रतिस्पर्धी फसलों की तुलना में मिलेट्स से प्राप्त लाभ एवं आय कम प्राप्त होती है।
3. हरित क्रांति के बाद धान और गेहूं के उत्पादन का अधिक समर्थन।
4. गुणवत्तापूर्ण बीज किसानों तक कठिनाई से पहुँच पते हैं।
5. कुल मूल्य श्रृंखला को पूरा करने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना जैसे प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, अद्वितीय मिलिंग उपकरण इत्यादि सुविधाओं की अपर्याप्तता।

नीति आयोग, भारत सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी), भारत मिलकर एमईजीपी पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका प्रमुख लक्ष्य एशिया तथा अफ्रीका में मिलेट्स को मुख्यधारा में लाने के लिए अच्छी प्रथाओं का संकलन और आदान-प्रदान करना है। यह पहल अच्छी प्रथाओं और प्रयासों के संकलन में मदद करेगी, और साथ ही साथ एशियाई और अफ्रीकी विकासशील देशों

1 शहरी भारत में बाजरा और ज्वार के खपत व्यवहार का आकलनः बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण, 2021।

2 पोषण सुरक्षा के लिए मिलेट्स मूल्य श्रृंखला: भारत से एक प्रतिकृति सफल मॉडल (2016)।

के बीच अपने अनुभव साझा करने हेतु एक अवसर भी प्रदान करेगी। भारत के साथ साथ विदेशों मे भी सरकार के लिए इसे सुगम बनाने हेतु अच्छी प्रथाओं के संकलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत तथा विदेश में सरकार यदि इन प्रथाओं एवं प्रयासों का विकास करने/दोहराने के लिए इच्छुक हैं, तो उसे बेहतर तरीके से समझने और निर्णयों को सक्रिय रूप देने में आसानी होगी। यह विभिन्न दक्षिण-दक्षिण सहकारिता (एसएससी) और दक्षिण-दक्षिण एवं त्रिकोणीय सहकारिता (एसएसटीसी) पथों को खोलेगा और अध्ययन यात्राएं, विशेषज्ञ तैनाती, प्रदर्शन साइट, समान स्तर के व्यक्तियों का कोचिंग नेटवर्क, प्रौद्योगिकी और/या ज्ञान अंतरण, और नीतिगत वार्तालापों के द्वारा आपसी सहयोग से नीतिगत विकल्प पेश करेगा।

इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अफ्रीकी एवं एशियाई राष्ट्रों के संगठनों एवं वृत्तिकों/व्यवसाइयों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो कि जमीनी स्तर से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक हो सकते हैं।

श्रेणियां

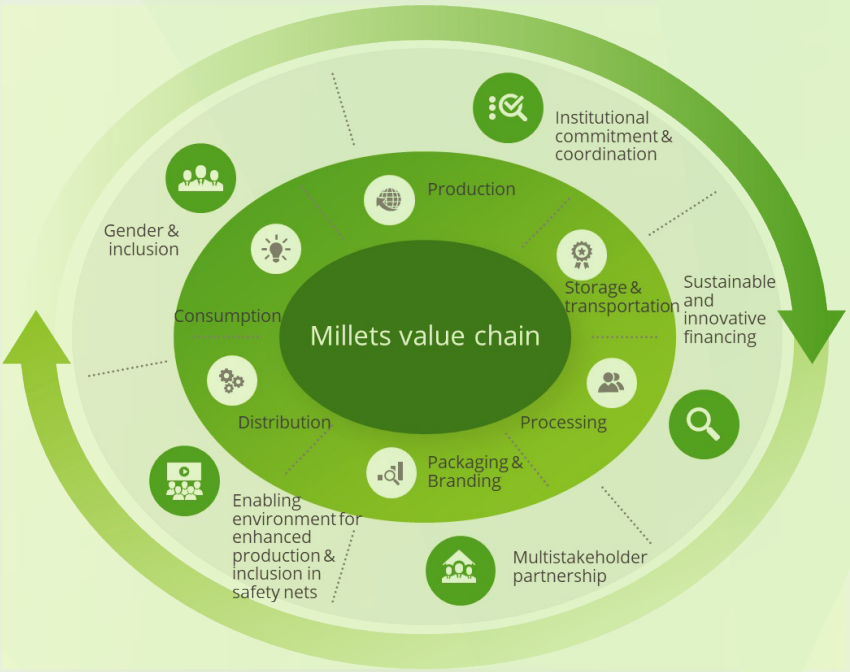

मिलेट्स के मुख्यधारा हेतु फ्रेमवर्क के अनुसार "एमईजीपी पहल" के लिए प्रविष्टियां दो मुख्य श्रेणियों में आमंत्रित की जाती है, जो निम्नलिखित है, (एक विस्तृत नोट संलग्न है)-

1. मिलेट्स की मूल्य श्रृंखला (उत्पादन, भंडारण और परिवहन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग, वितरण एवं खपत)
2. मुख्यधारा हेतु आयाम (संस्थागत प्रतिबद्धता और समन्वय, बहु-हितधारक साझेदारी, सतत एवं अभिनव वित्त पोषण, लिंग और समावेश एवं सुरक्षा जाल समावेशन हेतु पर्यावरण को तैयार करना।

मिलेट्स के विभिन्न व्यंजनों को तैयार करने एवं पकाने के तरीकों संबंधी अधिक जानकारी देने के लिए मिलेट्स के व्यंजनों की अलग श्रेणी होनी चाहिए, जिन्हें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में दैनिक आहार में शामिल किया जा सके।

समाधान और अच्छी प्रथाएं मांग और आपूर्ति पक्ष कारकों के अनुरूप और मिलेट्स के उत्पादन की कमी को पूरा करने वाले होने चाहिए।

हम भूली-बिसरी प्रथाओं, विशेष रूप से पारंपरिक और स्वदेशी प्रथाओं से अवगत कराने वाली प्रविष्टियों की भी सराहना करेंगे और इस पहल के माध्यम से अपने अनुभवों को साझा करने के लिए ऐसे वृत्तिकों, संगठनों और व्यक्तियों को प्रेरित करेंगे जो इस तरह की प्रथाओं के पुनरुद्धार के लिए काम कर रहे हैं।

पात्रता

सरकारी या गैर-सरकारी संगठनों, बहुपक्षीय या एफपीओ/एसएचजी/पीएसीएस और निजी क्षेत्र/स्टार्टअप और शिक्षाविदों को अंतःक्षेप की एक केस स्टोरी के साथ भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो कि किसी भू-भाग में परिकल्पित और कार्यान्वित की गई हो। संकल्पनात्मक स्तर पर समाधान मान्य नहीं होंगे। अफ्रीकी और एशियाई देशों से आमंत्रित प्रविष्टियां स्वीकार्य हैं।

प्रतिभागियों को लाभ

- मिलेट्स स्टार्टअप्स को बैक-सपोर्टिंग जैसी पहलों तक आसानी से पहुंच।
- विद्यार्जन के प्रसार के लिए क्षेत्रीय मंचों तक पहुंच।
- दानदाताओं, नवाचार प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थानों, सरकारी विभागों आदि सहित नेटवर्किंग प्लेटफार्मों तक पहुंच।
- संभावित स्केल-अप के लिए सरकारी विभागों के साथ संबंध"
- प्रकाशन एवं प्रचार प्रसार में सहयोग।

एमईजीपी पहल अच्छी पद्धतियों के प्रकाशन को एक साथ लाएगी, जिससे सभी योग्य प्रविष्टियों को सीखने और प्रसार हेतु मंच प्राप्त होगा। नवम्बर 2022 में क्षेत्रीय सम्मेलन के लिए निमंत्रण सहित आगे के समर्थन के लिए चयनित कुछ प्रविष्टियों को भी चयनित किया जाएगा। विजेताओं को कई विशेषज्ञों द्वारा मेंटरशिप सहायता प्रदान की जाएगी और यह पहल विजेताओं को दाताओं, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और सरकारी विभागों सहित प्रमुख हितधारकों से जोड़ेगी। विजेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण घटक ब्रिज पहल है जो संभावित स्केल-अप के लिए देश में विभिन्न सरकारी विभागों को समाधानों से जोड़ेगी।

मूल्यांकन मानदंड

- नवाचार (समाधान की नवीनता)।
- व्यावहारिकता (महत्वपूर्ण वर्तमान या उभरती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता)।
- लिंग और समावेशन (अंतिम छोर, सबसे अधिक हाशिए पर और शामिल न किए गए, विशेष रूप से महिलाओं तक पहुंचने की क्षमता)।
- प्रभाव (बड़े पैमाने पर परिणामों में सुधार की संभावना)।
- स्थिरता/टिकाऊपन (सार्वजनिक/निजी प्रणालियों के साथ स्केल-अप और संरेखण के लिए संभावित)।

समयसीमा

10 जुलाई 22: तैयारी, सोशल मीडिया रन-अप।

19 जुलाई 22 - एमईजीपी पहल का शुभारंभ वेब पोर्टल का उद्घाटन।

25 जुलाई -30 सितंबर 22 - आवेदन मांगने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रमों की एक श्रृंखला।

18 अक्तूबर 22 – आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि।

15 नवम्बर 22- प्रत्येक श्रेणी में शीर्ष 10 प्रविष्टियों की शॉर्टलिस्टिंग।

30 नवम्बर 22 - विजेताओं की प्रस्तुति और घोषणा।

दिसंबर 22 का चौथा सप्ताह - क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन। अच्छी प्रथाओं के संग्रह का शुभारंभ।

जनवरी 23 का तीसरा सप्ताह - ज्ञान प्रबंधन और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के लिए आमंत्रण।

निर्णायक समिति

अध्यक्ष

1. डॉ. शोभना पटनायक, भूतपूर्व कृषि सचिव, भारत सरकार और आईएफएडी के लिए भारत की ओर से अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार

सदस्य

1. डॉ.चिंदी वासुदेवप्पा, कुलपति, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम)।
2. सुश्री शुभा ठाकुर, संयुक्त सचिव (फसल एवं तिलहन), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
3. सुश्री श्रीदेवी अन्नपूर्णा सिंह, निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)।
4. डॉ. आर. हेमलता, निदेशक, राष्ट्रीय पोषण संस्थान-आईसीएमआर।
5. शेफ़ मंजीत गिल, अध्यक्ष, इंडियन फेडरेशन ऑफ क्यूलिनेरी एसोसिएशन।

सदस्य सचिव

1. डॉ. नीलम पटेल, वरिष्ठ सलाहकार (कृषि), नीति आयोग, भारत सरकार।
2. सुश्री प्रदन्या पैठंकर, प्रमुख- जलवायु लचीलापन, डीआरआर, एसएसटीसी, विश्व खाद्य कार्यक्रम, भारत।